Micro-project for development of tribals in Orissa

727. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the Micro-projects for development of Tribals in Orissa as on date;

(b) the funds allocated by Government to NGOs, District-wise, and

(c) the details of the activities undertaken by these NGOs in the State, so far, and the number of persons benefited during each of the last three years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) Seventeen micro projects are functioning for welfare and development of Primitive Tribal Groups in Orissa.

(b) and (c) Under the Central Sector Scheme of grant in aid to NGOs, Rs.79.04 lakhs, Rs. 149.41 lakhs and Rs.9551 lakhs were provided to different NGOs in the State of Orissa during the years 1995-96, 1996-97 and 1997-98 respectively for the welfare and development of Scheduled Tribes. With these grant in aids various activities such as residential schools, orphanages, library, hostels, balwadies, creches, medical units, computer training, shorthand and typing training, kanyashram etc were undertaken to benefit about 23,000 tribals annually for each year of last three years. These grant in aids are not given to NGOs district wise.

जनजातीय क्षेत्र कल्याण निधि

728. **श्री चीमनभाई हरी भाई शुक्ला**: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय क्षेत्र कल्याण निधि(जनजातीय उपयोगता) के लिए धनराशि में भारी कमी / गिरावट आई हैं;

(ख) यदि हां,तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को गुजरात से कुछ कल्याण योजनाएं प्राप्त हुई हैं ;

(घ) यदि हां,तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;और

(ड़) सरकार द्वारा गुजरात में कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के द्वारा बेसहारा बच्चों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या उदम उठाए गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी,नहीं । आदिवासी उप योजना प्रवाह वर्ष 1996-97 की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान पूर्ण अर्थ तथा राज्य योजना के प्रति प्रतिशतता दोनों के लिए उच्चतर रही हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ड़) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बेसहारा बच्चों,ख़ास कर वे जो बेघर तथा बिना पारिवारिक बंधनों के हैं, के बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक गैर संस्थागत समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से बेसहारा बच्चों के लिए एक समेकित कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों,स्थानीय निकायों,सहकारी समितियां,शैक्षिक तथा अन्य संस्थाओं और अन्य गैर सरकारी संगठनों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है । वर्ष 1998-99 के दौरान,गुजरात में अब तक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 10 गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की गई है । तथा 31.68 लाख रू. की धनराशि उन्हें निर्मुक्त की गई हैं ।

Schemes for uplimfment of SCs, STs and minorities

729. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the details of Welfare Schemes/ programmes being formulated and implemented in the country by Government for the uplftment of *SC,* ST and minorities Communities;